भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4562
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
29 श्रावण, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग

4562. श्री बी. के. पार्थसारथीः
श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा विशेष रूप से शुरू की गई क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश में ऐसे और अधिक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राज्य के लिए नियोजित नई क्षमता-निर्माण परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे कार्यक्रमों को वार्षिक या नियमित प्रशिक्षण पहल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में इन क्षमता-निर्माण पहलों के लिए आवंटित या आवंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी), सरकार के सभी स्तरों पर डिजिटल गवर्नेंस क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। ये पहल उन्नत, भूमिका-विशिष्ट और प्रौद्योगिकी-उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। दिसंबर 2023 और जुलाई 2025 के बीच, एनईजीडी ने आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विशाखापत्तनम और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), पलासमुद्रम में होस्ट किए गए आठ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए।

आयोजित कार्यक्रमों में शामिल थे:

- डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल गवर्नेंस पहलों की देखरेख और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए *बड़े डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के प्रबंधन* पर तीन कार्यक्रम ;
- उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के लिए *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोगों* पर तीन कार्यक्रम ;
- *आईटी परियोजना प्रबंधन और ई-गवर्नेंस* पर दो कार्यक्रम ।

दिसंबर 2023 से, आईआईएम विशाखापत्तनम में अगले तीन वर्षों तक हर साल चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन क्षमता निर्माण पहलों के लिए आंध्र प्रदेश के लिए अलग से कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

****